Regarding alleged harassment of minorities in Malegaon, Maharashtra.-laid

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान मालेगांव शहर में अल्पसंख्यकों के जांच के बहाने हो रहे कथित उत्पीड़न की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । वर्तमान में मालेगांव में एक विशेष जांच दल अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की उपस्थिति के संबंध में जांच कर रहा है । 45 दिनों से अधिक की जांच के बाद भी किसी भी अवैध प्रवासी की उपस्थिति नहीं पाई गई है । जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जारी करना बंद कर दिया गया है । अल्पसंख्यकों के लिए माहौल असहज हो गया है । भारतीय होने के नाते, हम सभी जांच अधिकारियों के प्रयासों का समर्थन करते हैं, जो देश की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिन-रात काम करते हैं । लेकिन, जांच के दौरान ईमानदार भारतीय नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए । अनुच्छेद 21 के तहत, सभी भारतीयों को, अमीर-गरीब, बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार प्रदान किया गया है । मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह तत्काल कार्रवाई कर मालेगांव में अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न पर रोक लगाए तथा ईमानदार भारतीयों की सुरक्षा और निजता की रक्षा करे ।